क्रीडा का गठन कर होगा कायाकल्प, KDA को मिली कंसल्टेंट चुनने की जिम्मेदारी

कानपुर समेत 8 जिलों के विकास को दिशा देगा 'रीजनल प्लान 2051'

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

कानपुर के साथ उसके आसपास के आठ जिलों को मिलाकर दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर विकास का खाका खींचा जाएगा। इसके लिए कानपुर देहात, कानपुर नगर, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, औरैया और कन्नौज को मिलाकर कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड अथॉरिटी (क्रीडा) का गठन होगा। इसका जिम्मा कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) को दिया गया है। तय योजना के मुताबिक क्रीडा के लिए कंसल्टेंट का चयन किया जाएगा और उसकी सिफारिश के मुताबिक कानपुर समेत इसके पड़ोसी आठ जिलों को मिलाकर 'रीजनल प्लान 2051' का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद इस ड्राफ्ट की सिफारिशों के मुताबिक कानपुर समेत पड़ोसी आठ जिलों में इस तरह विकास कार्य किए जाएंगे ताकि हर जिला रोजगार और औद्योगिक विकास के प्रॉजेक्ट्स से जुड़ सके।

क्या फायदा होगा

इस पूरे क्षेत्र में जमीनों के बेहतर प्रबंधन, आवास के साथ ही उद्योग और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े प्रॉजेक्ट्स को लेकर बेहतर योजनाएं बनाई जा सकेंगी।

यूपी में दिल्ली एनसीआर के मॉडल पर डिवेलपमेंट का रोडमैप तैयार किया गया है। इसके तहत मंडल के मुख्यालय या पहले से विकसित बड़े जिले के पड़ोसी जिलों को मिलाकर एक स्पेशल इकॉनमिक जोन बनाया जाएगा। इसके तहत लखनऊ को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र के बाद अब यूपी के सबसे पुराने औद्योगिक शहर कानपुर को उसके पड़ोसी जिलों के साथ मिलाकर कानपुर रीजनल इंटीग्रेटेड अथॉरिटी (क्रीडा) बनाने का फैसला हुआ है। इसके तहत कानपुर समेत पड़ोसी आठ जिलों को मिलाकर कुल 20,094 किमी वर्ग क्षेत्र में विकास से जुड़े प्रॉजेक्ट को नया मुकाम दिया जा सकेगा।

आवास विभाग के सूत्रों की मानें तो कानपुर के बाद वाराणसी और प्रयागराज मंडल में भी उनके आसपास के जिलों को मिलाकर रीजनल डिवेलपमेंट अथॉरिटी गठित की जाएगी।

राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए 'कार्यकारी समिति' गठित

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ** : लखनऊ को मिलाकर बनने वाले 'राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण' के लिए शासन ने कार्यकारी समिति का गठन कर दिया है। अब यह समिति ही इस विकास क्षेत्र प्राधिकरण का काम देखेगी। माना जा रहा है कि जल्द ही कंसल्टेंट का चयन किया जाएगा। यह कंसल्टेंट ही राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के दायरे में आने वाले जिलों को मिलाकर विकास का खाका खींचते हुए प्रस्ताव बनाएगा। इस बीच सरकार ने उप्र राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी समेत 22 सदस्यों का ऐलान कर दिया है। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है।